P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-6* ISSUE-3* June- 2021
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

बैंकों के निजीकरण का औचित्य
The Rationale for Privatization of Banks

Paper Submission: 02/06/2021, Date of Acceptance: 14/06/2021, Date of Publication: 23/06/2021

रीता सिंह
सहायक प्राध्यापक,
अर्थशास्त्र विभाग,
एम.जी. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरसिया,
रायगढ़, छत्तीसगढ, भारत

सारांश

बैंकों का एक मात्र लक्ष्य लाभ नहीं होता। अतः निजीकरण कर देने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता, इसके लिए विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना होगा और विद्यमान कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

अगर सरकार आर्थिक विकास को लेकर गंभीर है तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत किया जाना चाहिए। बैंकों के निजीकरण का सरकार की कल्याणकारी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

Banks do not have the only motive of earning profits. Therefore privatization cannot be the soulution. Thus Government will have to look into it with a broad view and try to find out the shortcomings in the ongoing system.

If Government is serious on economic growth then public sector banks should be strengthened. Privatization of banks will have negative effect on the welfare policy of the Government.

मुख्य शब्द : निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीयकरण, राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद।

Privatization, Public Sector, Economy, Nationalization, Revenue Receipts, Fiscal Deficit, Gross Domiestic Prduction (GDP).

प्रस्तावना

आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के अंतर्गत वर्ष 1992 से भारत सरकार द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में निजी बैंकों के प्रवेश की अनुमति दे दी गई है अब एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात निजी बैंक भारत में अपना कारोबार कर सकते हैं।

यह बैंक कंपनी अधिनियम 1956 (वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013) के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं तथा इन पर बैंकिंग नियमन अधिनियम तथा रिजर्व बैंक अधिनियम लागू होता है। इन बैंकों की पूंजी 200 करोड़ रूपये की होती है तथा इनके अंश प्रतिभूति बाजार में लिस्टेड होते हैं।

जहां तक बैंकों के निजीकरण की बात है तो कुछ लोगों को लगता है कि बैंकों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसे निजी हाथों में दे दिया जाना चाहिए।

यहां इस बात को समझना महत्वपूर्ण हैं कि सरकारी बैंकों की शाखाएं दूरदराज की ऐसी जगहों पर भी होती हैं जहां निजी बैंक पहुंचना पसंद नहीं करते। ऐसे में सरकारी बैंक गांव देहात में सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाते हैं। ऐसे में इन बैंकों पर निर्भर गरीबों के लिए बैंकों के निजीकरण का क्या अर्थ होगा।

1947 के पहले देश में निजी संस्थाएं ही वित्तीय लेनदेन का कार्य करती थीं। यह जरूर था कि उनकी ब्याज दर अधिक होती थी, किन्तु कृषि छोटे उद्योग तथा निर्यात में वृद्धि को बढ़ावा देने नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार 29 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का और 5 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का किया गया।

सरकार ने समय–समय पर बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ–साथ इन्हीं उद्देश्यों के चलते कुछ बैंकों का विलय भी किया है, नरसिम्हन समिति तथा पी. जे. नायक समिति में बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए बैंकों के विलय की सिफारिश की है।

अध्ययन विधि(Methodology)

अध्ययन की विधि विश्लेषणात्मक है जिसमें द्वितीयक समंकों का प्रयोग किया गया है। विभिन्न लेखकों की पुस्तिकों और वेबसाइट से सामग्री का संकलन कर प्रामाणिक तरीके से विवेचन करने का प्रयास किया गया है।

साहित्यावलोकन (Review of Literature)

1. के. रामकुमार (30 मार्च 2021 में)–अपने अध्ययन में सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण में सूची का अनुमान लगाया है।
2. सीमा चौधरी (9 अप्रैल 2021)– सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण विषय पर अध्ययन किया है।
3. अनुषा चारी (9 मार्च 2021)– सार्वजनिक या निजी ? भारत और अमेरिका में बैंकिंग के भविष्य में दोनों अपने अपने देश में वित्तीय समायोजन और उधार का इष्टतम मिश्रण का अध्ययन किया गया है।
4. सुबीर रॉय (10 जून 2020)– निजीकरण पीएसबी के लिए रामबाण नहीं है का अध्ययन किया है।

निजीकरण के उद्देश्य (Object of Privatization)

1. ऐसा कहा जा रहा है कि बैंकों के निजीकरण किया जाने से कार्य का निष्पादन अधिक कुशलता से होगा।
2. शिक्षित और उद्यमशीलता युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।
3. राजकोषीय संतुलन को बिगाड़ने वाले घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमों को समाप्त करके राजकोषीय घाटे को समाप्त करना।
4. विदेशी ऋणों पर निर्भरता को कम करके निर्यात संवर्धन करके विदेशी मुद्रा में वृद्धि करना।
5. प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना।
6. अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा का संचार करना।
7. ऐसा माना जा रहा है कि निजीकरण के द्वारा प्रशिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार की अपार संभावनाएं उत्पन्न होती है।
8. कर्मचारियों की लालफीताशाही कम होगी।
9. बैंकों की लाभांश में वृद्धि होकर देश के आर्थिक विकास में वृद्धि होती है।
10. सरकार पर वित्तीय दबाव कम होगा, क्योंकि निजीकरण के बाद बैंक अपनी पूंजी स्वयं जुटायेंगे।
11. सरकार को पैसा चाहिए ताकि वह दूसरे खर्चों को पूरा कर सके।

निजीकरण के लाभ (Benefits of Privatisation)

1. बाजार के हिस्सेदारी में बढ़ोत्तरी

बैंकों द्वारा विवरण दिये जा रहे हैं, उनमें निजी बैंकों की हिस्सेदारी 2015 में 21.26% से बढ़कर 2020 में 36% हो गई है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की हिस्सेदारी 72.28% से गिरकर 59.8% पहुंच गई है।

2. बेहतर उत्पाद और सेवा

90 के दशक में बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश से नए उत्पादों, प्रौद्ययोगिकी और बेहतर सेवाओं के माध्यम से निजी बैंकों ने बाजार में अपनी पैठ बनाई है।

3. बैंकों के निजी करण से सरकारी संसाधनों और धन की बर्बादी कम होती है।
4. निजीकरण से अनुशासन में वृद्धि होगी तथा ग्राहकों को समुचित सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।
5. निजीकरण करने से बड़े बैंक निकल कर आएंगे और ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करेंगे।

निजीकरण के दोष (Limitations of Privatisation)

1. बैंकों के निजीकरण का सबसे बड़ा दोष यह है कि इससे तानाशाही को बढ़ावा मिलेगा।
2. सरकार द्वारा निर्धारित सामाजिक उद्देश्यां की पूर्ति नहीं हो पाएगी।
3. आम जनता, गरीब जनता को बेहतर सुविधाएं प्राप्त नहीं होगी।
4. कर्मचारियों में अंसतोष बढ़ेगा पर वे उसका खुलकर विरोध नहीं कर पाएंगे।
5. निजीकरण के परिणाम स्वरूप बैंक कुछ बड़े घराने तक सीमित रह जायेंगे।

निजीकरण के प्रभाव (Effects of Privatisation)

सरकार ऐसा मानती है कि उसे समय–समय पर बहुत ज्यादा पूंजी सार्वजनिक बैंको में लगाना पड़ता है। जिसकी वजह से सरकार के बाकी कार्य प्रभावित होते हैं अतः निजीकरण इसके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

परन्तु भारत जैसे देश में जहां बैंकिंग कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है ऐसे में निजीकरण करने से कर्मचारियों के सामने बेरोजगार हो जाने का जोखिम बढ़ जाता है साथ ही हड़ताल के चलते करोड़ों रूपय का लेन–देन प्रभावित होता है, ए.टी.एम. में पैसा नहीं निकलता, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को भी परेशानी झेलनी पड़ती है।

बैंकिंग सेक्टर में सरकारी बैंकों के निजीकरण का फैसला राजनीतिक रूप से भी जोखिम भरा कदम हो सकता है, अभी सरकार जिन दो बैंकों के निजीकरण की बात कर रही है उसका आगे परिणाम यह भी हो सकता है कि 12 बैंकों में से 2 का सफल निजी करण होने पर बाकी के 10 में से भी निजी करण करके सार्वजनिक बैंकों की संख्या 4–5 तक कर दी जाए। जब बैंकों का निजीकरण किया जाएगा तो जो भी व्यक्ति या संस्था बैंक खरीदेगी वह भी अपना मुनाफा देखेगी क्योंकि कोई भी निजी उद्यमी बिना लाभ के काम नहीं करता है ऐसे में सबसे पहले वह बैंक के खर्चों में कटौती करेगी दूसरी तरफ जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि 20 वर्ष हो चुकी है उन्हें भी स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए बाध्य कर सकती है।

सुझाव (Suggestions)

मेरे हिसाब से बैंक का काम मुनाफा कमाना नहीं है बल्कि इसका सामाजिक रोल भी है।

इतिहास पर हम नजर डालें तो निजी बैंक केवल बड़े–बड़े रईसों के लिए है अगर निजीकरण करना ही था तो राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया क्योंकि निजी बैंक देशहित नहीं बल्कि अपने हित की परवाह करते हैं इसलिए यह फैसला ना सिर्फ कर्मचारियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए खतरनाक है।

फिर पिछले कुछ सालों में प्राइवेट बैंकों की गड़बड़ियों भी सामने आई है इसलिए यह कहा जा सकता है कि निजी बैंकों में बेहतर काम नहीं होता।

जब भी कोई बैंक पूरी तरह डुबने की हालत में पहुंच जाता है तब सरकार को ही आगे उसे बचाना पड़ता है, और तब यह कार्य किसी ना किसी सरकारी बैंक के मत्थे मढ़ दी जाती है। यही वजह है कि आजादी के बाद से आज तक भारत में कोई अनुसूचित व्यापारिक बैंक नहीं डूबा है।

फिर भी कुछ को लगता है कि बैंकों का निजीकरण यानी बैंकों को निजी हाथों में दे दिया जाना ही इस समस्या से निपटने का सही तरीक है।

यहां इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि सरकारी बैंकों की शाखाएं दूरदराज की ऐसी जगह पर भी होती हैं जहां निजी बैंक पहुंचना पसंद नहीं करते साथ ही सरकारी बैंक गांव–देहात तक में सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाते हैं ऐसे में इन बैंकों पर निर्भर रहने वाले गरीबों के लिए सरकारी बैंकों के निजीकरण के क्या मायने हैं।

कभी–कभी बड़े कर्जे की भरपाई ना होने के कारण बैंक फेल हो जाते हैं लेकिन ऐसे में सरकार को उसको बचाने के लिए सामने आना पड़ता है।

सरकारी बैंकों के मामले में सरकार अगर बैंक के लिए पैसे देती है तो इसे गलत करार दिया जाता है, लेकिन बैंक चाहे सरकारी हो या निजी उसमें छोटे–बड़े हर तरह के वर्ग के लोगों के जीवन भर की पूंजी होती है। अगर निजी बैंक फेल हो गये तो सरकार को ही मदद के लिए आगे आना पड़ता है।

बैंकों के निजीकरा से जनता को तो नुकसान होगा ही, बैंक कर्मियों को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जबकि जब भी किसी देष में त्रासदी आती है तो यह बैंक कर्मी विभिन्न तरीकों से सहयोग प्रदान करते हैं। देष की, सरकाार की किसी भी नीति को व्यवहारिक रूप देने का कार्य बैंक करती है, और जब बैंक का सवाल आता है वह चाहे मजदूरी हों, पेंषन हो या उनकी सुरक्षा का उन्हें गुमराह कर दिया जाता है।

हम यह जरूर कहते हैं कि बैंकों का प्रदर्शन अच्छा नहीं है, जबकि यह बैंक पहाड़ में रेगिस्तान में और भी ऐसे जगह पर काम कर रहे हैं जहां सिर्फ 2 स्टाफ है वहां वे किस स्थिति में काम कर रहे हैं उसकी व्यवहारिकता को कोई नहीं समझता। और इसके बाद भी यह ढोल पीटा जाता है कि बैंक घाटे में है, जबकि बैंक के घाटे का मुख्य कारण कारपोरेट है जो अधिक मात्रा में लोन में लेती है और वाापस नहीं करती है और कहा जााता है कि बैंक घाटे में चल रही है।

जब निजीकरण करना ही था तो राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया ? ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें निजी बैंक जनता का पैसा लेकर भाग गए, पिछले वर्ष यस बैंक मुसीबत में था, फिर लक्ष्मी विलास बैंक का अधिग्रहण एक विदेशी बैंक ने किया है, आईसीआईसीआई बैंक भी समस्या ग्रस्त है, इन सबके बाद भी सरकार बैंकों के निजीकरण पर जोर दे रही है सार्वजनिक बैंक को निजी बैंक को बेच रही है।

सरकार को अपने निजी करण के फैसले पर संजीदगी से विचार करना होगा क्योंकि देश युवाओं का है और जिस देश में युवा बेरोजगार रहेगा उस देश के आर्थिक उन्नयन की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

बैंकों का निजीकरण एक बुरा विचार है अगर सरकार आर्थिक विकास को लेकर गंभीर है तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को मजबूत किया जाना चाहिए। सार्वजनिक हित में लोगों के हित में, देश के हित में मैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का विरोध करते हैं। निजीकरण का विरोध करते हैं। निजीकरण करने से पहले सरकार को कर्मचारियों की संख्या, ट्रेड यूनियन का दबाव और राजनीतिक तनाव के आकलन के बाद ही देश हित में अंतिम फैसला लिया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *दत्त एवं सुंदरम (1965)*
2. *भारतीय अर्थव्यवस्था एस.चंद एंड कंपनी प्रा. लि.*
3. *drishtias.com*
4. *bbc.com*
5. *hindilibraryindia.com*
6. *माहेश्वरी एवं गुप्ता ''भारतीय आर्थिक नीति''– कैलाश पुस्तक सदन*
7. *hindi.news18.com*
8. *भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह McGraw Hill Education (India) प्राईवेट लिमिटेड*
9. *hindi.gktody.in*